ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

बेवकूफी का पर्याय उल्लू की जान खतरे में

रविवारीय, 27 अक्टूबर - 02 नवंबर 2019, वर्ष- एक, अंक-12, रांची | हिन्दी साप्ताहिक | R.N.I. No. JHAHIN 00962 | कुल पृष्ठ 4 | मूल्य 2 रूपये

सभी प्रिय पाठकों को ग्रीन रिवोल्ट परिवार की ओर से दीपावली एवं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनायें

झारखंड की धरती और मौसम फूलों की खेती के लिये है सबसे अनुकूल, फिर भी यहां बंगाल से आते है फूल

बंगाल के फूलों से गुजलार रांची

वरीय संवाददाता

रांची : पर्व त्यौहार हों या शादी विवाह या फिर कोई इवेंट सबों में फूलों की आवश्यकता होती है। इन सभी मौकों पर फूलों के खपत के कारण रांची में फूलों का एक अच्छा खासा बाजार है। और यह अनदेखा सा बाजार वार्षिक रूप में करोड़ो का है।

रांची में हम जितने भी फूल बाजार में देखते हैं ये सब के सब बंगाल से मंगाये जाते हैं। और इनकी डिमांड तकरीबन सालो भर रहती है। बंगाल में इनकी खेती उन्नत तरीके से होती है और वहां की मिट्टी में इनकी उपज भी अच्छी है। लेकिन इससे भी मुख्य बात ये है कि झारखंड में इन फूलों की अच्छी खेती के लायक मौसम और मिट्टी बंगाल से भी अच्छी है। ये दुर्भाग्य है, कि प्राकृतिक रूप से बेहतरीन स्थिति में होने के बाद भी यहां के किसान फूलों की खेती पर ध्यान नहीं दे पाये हैं। हालांकि लोहरदगा, मांडर जैसे कुछ अन्य जगहों पर गेंदे की खेती हो रही है और कुछ अन्य जिलों में भी इनकी खेती के प्रयास शुरू किये गये हैं, पर आज भी फूलों की आपूर्ति मुख्य रूप से बंगाल से ही होती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रयास है कि, झारखंड के किसान फूलों की खेती आधुनिक तरीके से करें।। उसके लिये प्रशिक्षण से लेकर मदद का भी प्रावधान है, लेकिन अभी तक संतोषजनक फल नहीं मिल पाया है।

झारखंड में फूलों की खेती की बहुत गुंजाइश है: डॉ. के. के. झा (हेड हॉर्टीकल्चर, बीएयू, रांची)

राज्य में बंगाल से भी ज्यादा फूलों के पैदावार की जा सकती है। भले अभी फूलों की आवक बंगाल से हो रही है, पर हमारा प्रयास है कि अगले कुछ सालों में राज्य फूलों की खेती में आत्मनिर्भर हो जाये। कुछ जगहों पर फूलों की अच्छी खेती हो रही है। लेकिन वह राज्य में डिमांड की पूर्ति नहीं कर पा रहा। छोटानागपुर रीजन का मौसम फूलों की खेती के लिये बेहतरीन है। बाजार में दो प्रकार के फूलों की बिक्री होती है। कट एवं लूज फ्लावर। लूज फूल में गेंदा वगैरह हैं इनका उपयोग पूजा करने एवं माला वगैरह बनाने के लिये किया जाता है। वहीं कट फ्लावर में वैसे फूल आते हैं जिन्हें गुलदस्ते में या प्लास्टिक में पैक किया जाता है। अभी यहां समस्या आ रही है कि कट फ्लावर पॉली हाउस के अंदर उपजाये जाते हैं, जिसे बनाने में ज्यादा खर्च आता है और आंधी तूफान आ जाने पर इसके क्षतिग्रस्त होने का नुकसान छोटे किसान नहीं उठा पाते। फिर भी हम तेजी से फूलों की खेती को विकसित कर रहे हैं। हमें झारखंड के सुदूर इलाकों से पैकिंग और ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि किसानों की उपज समय पर बाजार में आ सके।

सालो भर है फूलों का बाजार : राजू सरकार

रातू रोड दुर्गा मंदिर के पीछे रांची का सबसे बड़ा फूल बाजार है। यहां के एक फूल विक्रेता राजू सरकार ने कहा कि भादो जैसे महिने को छोड़ दें तो सालो भर फूलों की डिमांड रहती है। पर्व त्यौहारों, आयोजनो और लगन के कारण इसका बाजार हमेंशा रहता है। अभी दशहरे दिवाली में मांग बढने के साथ ही सबसे ज्यादा खपत गेंदे के फूलों की है। इसके अलावा गुलाब और रजनीगंधा की डिमांड रहती है। हम फूल कोलकाता से मंगाते हैं। कुछ फूल बहुत महंगे हैं जैसे लिली और आर्किड। इस कारण से इन की डिमांड कम है और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। लिली के एक फूल की कीमत दो सौ रूपये भी हो सकती है। झारखंड सरकार ने अपने आयोजनों में बड़े गुलदस्तों के लेन देन पर रोक लगा दी है, इसके बावजूद फूलों की डिमांड में कोई कमी नहीं है। हालांकि यह कच्चा व्यवसाय है, इसमें फूलों को लंबे समय तक हम स्टोर नहीं कर सकते, फिर भी डिमांड ऐसी है कि हम कोलकाता से रेगुलर मंगाते ही रहते हैं।

18 वर्ष में 13 लाख असंगठित मजदूरों का हुआ निबंधन

संवाददाता

- ऐसे काम करती है वर्तमान सरकार...रघुवर दास
- नगर निगम के तहत सड़क एवं नाली सफाई कार्य से जुड़े निबंधित श्रमिकों के बीच पैंट-शर्ट का कपड़ा तथा साड़ी का वितरण किया गया
- रोजगार मेले में विभिन्न प्रतिष्ठानों व एजेंसियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया
- आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में 500 व सहायिका के मानदेय में 250 रुपये की वृद्धि
- 92 प्रतिशत असंगठित मजदूरों की आवाज सरकार बनेगीः रघुवर दास

मोरहाबादी मैदान/रांची : जिस तरह हम सत्यमेव जयते कहते हैं उस प्रकार "श्रममेव जयते" भी कहना चाहिए। श्रम बड़ी पूंजी है। इसके बिना हम कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते। पूंजी बढ़ाने और राज्य को समृद्धशाली बनाने के लिए श्रम की बड़ी भूमिका है, इसको नकारा नहीं जा सकता। अगर ये मजदूर और सफाईकर्मी नहीं होते तो अपना झारखण्ड स्वच्छ नहीं रहता। हमारे शहर को स्वच्छ बनाने वाले और निर्माण में महती भूमिका निभनेवालों को इस दीपावली सरकार ने उपहार स्वरूप पुरुषों को पैंट-शर्ट का कपड़ा और महिलाओं को साड़ी और ब्लाउज देने का निर्णय लिया। उसी के निमित आज हमसब यहां हैं। आप सभी को पैंट- शर्ट के सिलाई के लिए 500 रुपये एवं ब्लाउज की सीलाई हेतु 100 रुपये श्रम विभाग प्रदान करेगा। आपको ठंड से बचाने के लिए सरकार स्वेटर भी देगी। गरिमा से आप भी जीवन जीएं। यह सरकार का लक्ष्य है। क्योंकि 8 प्रतिशत संगठित मजदूरों की आवाज उनकी यूनियन है। जबकि 92% असंगठित मजदूरों की आवाज कोई नहीं। ऐसे मजदूरों की आवाज वर्तमान सरकार बनेगी। सरकार आपको अपने परिवार का हिस्सा मानती है। असंगठित मजदूरों को भवन निर्माण विभाग से जोड़ने हेतु 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि आप अर्द्धकुशल मजदूर का दर्जा प्राप्त करें और आप को मिलने वाली राशि में तत्काल 500 रुपये की बढ़ोतरी हो जाए। ये बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने मोरहाबादी मैदान में आयोजित श्रम सम्मान समारोह एवं दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मियों को लोग निम्न प्रवृत्ति के मजदूर के रूप में देखते हैं। समाज को अपनी मनोवृति बदलने की जरूरत है। अगर ये सफाई कर्मी नहीं होते तो हमारा शहर, हमारा राज्य गंदगी से पट जाता। ये भी भारत माता की संतान हैं, इनकी चिंता भी सभी करनी चाहिए। शेष पेज 3पर

सूचना

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

दिव्यांगों को रोजगार मिलता देख मन भर आया :मुख्यमंत्री

खेलगांव/रांची : अपने जीवन में नई शुरुआत कर रही बेटियों को शुभकामनाएं। आप सभी की दीपावली शुभ हो। झारखण्ड की बच्चियों को यहीं रोजगार मिले। उन्हें रोजगार के लिए अन्य राज्य में पलायन ना करना पड़े। इसके लिए वर्तमान सरकार ने बेहतर नीतियां बनाई। क्योंकि रोजगार के नाम पर राज्य की बच्चियों को बेच दिया जाता था। रोजगार के नाम पर उनका शारीरिक शोषण होता था। मुझे इससे बड़ी पीड़ा होती थी। बच्चियों को यही रोजगार मिले। इस को लक्ष्य बनाकर हमने वस्त्र उद्योग स्थापना हेतु पॉलिसी बनाई और आज धनतेरस के अवसर पर बच्चियों को रोजगार प्राप्त करता देख आंतरिक खुशी हो रही है। सरकार का यही प्रयास था कि जॉब ओरिएंटेड पॉलिसी बने। ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिलने में किसी तरह की परेशानी ना हो। ये बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने होटवार इंडस्ट्रियल एरिया खेलगांव में ओरिएंटल क्राफ्ट की नवनिर्मित आधुनिक वस्त्र उद्योग इकाई के उद्घाटन समारोह में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को विकासशील राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में लाना है और वस्त्र उद्योग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन द्वारा व्यावसायिक उत्पादन से लाभ

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक खेती को लाभकारी व्यवसाय का स्वरुप देने की ओर प्रयासरत

संवाददाता

कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन द्वारा व्यावसायिक उत्पादन से लाभ फसल को सीधे बाजार में बेचने से काफी कम मुल्य मिलता है और फसल लागत की तुलना में ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। कई ऐसे फसल हैं, जिनका वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन द्वारा उत्पादों को तैयार कर बेहतर आय का साधन बनाया जा सकता है। कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक खेती को लाभकारी व्यवसाय का स्वरुप देने की ओर प्रयासरत है। इसके लिए विभाग द्वारा किसानों विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा यूजीसी से मान्यता प्राप्त तीन वर्षीय बैचलर ऑफ़ वोकेशनल इन ह्यूमन न्यूट्रीशन एंड डायेटेटिकस पाठ्यक्रम भी दो वर्षो से चलाया जा रहा है। विभाग के द्वारा अध्ययनरत कृषि स्नातकों को भी अनुभवीजन्य शिक्षा कार्यक्रमों के अधीन स्वरोजगार के रूप में अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष बताती है कि विश्वविद्यालय में अध्यनरत स्नातक छात्र - छात्राओं के इस दल में रोहित कुमार,पूजा कुमारी,खुशबू स्वर्ण,राधेश्याम यादव,विभांशु दिब्याल,संजय कुमार,रुपेश कुमार और भितेश कुमार मण्डल को अनुभवीजन्य शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किया।

छात्रों को गृह विज्ञान विभाग के प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन ईकाई में मडुआ (रागी) के विभिन्न

जानकारी

देसी भारतीय गाय का दूध विदेशी गायों से बेहतर

सुरिंदर सूद

क्या स्वदेशी भारतीय गायों का दूध विदेशी नस्ल वाली गायों से बेहतर है? अगर दूध की गुणवत्ता और उसमें निहित प्रोटीन तत्त्वों के संयोजन की बात करें तो इसका जवाब 'हां' है।

बीटा-केसीन में ए1 और ए2 दूधों में समान रूप से पाए जाने वाले 209 अमिनो अम्लों की एक शृंखला होती है। लेकिन 67वें स्थान पर स्थित अमिनो अम्ल दो मामलों में अलग होता है। जहां ए2 बीटा-केसीन का इंसानी दूध की तरह इस स्थिति में उपयोगी प्रोलाइन होता है वहीं ए1 में हिस्टीडाइन होता है जो पाचन के दौरान अस्वास्थ्यकर पेप्टाइड बीसीएम-7 में टूटने की प्रवृत्ति रखता है। आम तौर पर 'दूध का शैतान' कहा जाने वाला यह पेप्टाइड मॉर्फीन से समानता रखता है जो कि मस्तिष्क के लिए बेहद नुकसानदायक है।

भारत समेत अधिकांश एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में विकसित पशु नस्लों से निकलने वाला दूध मूल रूप से ए2 किस्म का ही है। इसके उलट यूरोपीय (फ्रांस को छोड़कर), ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका में विकसित नस्लों के मवेशी सामान्य तौर पर ए1 दूध ही पैदा करते हैं। कुछ मामलों में उनके दूध में ए1 और ए2 बीटा-केसीन का मिश्रण होता है लेकिन मोटे तौर पर यह ए1 श्रेणी वाला दूध ही होता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि बचपन में ए1 दूध के सेवन का संबंध टाइप-1 डायबिटीज, दिल की बीमारी, पाचन अनियमितता और ऑटिज्म जैसी बीमारियों से जुड़ा हो सकता है। ऑटिज्म एक मानसिक अवस्था है जिसमें लोग सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा होने से बचते हैं और बार-बार एक ही आचरण दोहराते रहते हैं। लेकिन ए2 श्रेणी वाले दूध के सेवन से इस तरह की बीमारियां होने का कोई नाता सामने नहीं आया है। सामान्य दूध को लेकर असहज लोग भी ए2 दूध का सेवन कर सकते हैं।

असल में, गाय ए2 दूध का अकेला जरिया नहीं है। भैंस, बकरी, भेड़, याक और ऊंट जैसे दूसरे दुधारू पशुओं से भी ए2 दूध मिलता है। यही वजह है कि इन मवेशियों के दूध को बाजार में खास स्थान मिलता है। कूबड़ वाले कुछ पशुओं, मसलन ऊंटनी से निकले ए2 दूध की कुछ किस्में ऑटिज्म पर काबू पाने और उसके लक्षणों को पूरी तरह दूर करने के लिए भी मुफीद मानी जाती हैं। इस मान्यता के कारण भारत समेत कई देशों में ऊंटनी के दूध की मांग एवं मूल्य दोनों में काफी तेजी आई है। लेकिन इनमें से अधिकांश दावों की पुष्टि के लिए अभी और अध्ययन किए जाने की जरूरत है। हालांकि यह सच है कि देसी गाय का दूध ए2 किस्म वाला होने के दावे को वैज्ञानिक तौर पर पुष्ट किया जा चुका है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (एनएएएस) ने हाल ही में जारी रणनीति पत्र में इसे स्वीकार भी किया है। 'भारत में ए1 एवं ए2 दूध की पूर्ण क्षमता का दोहन' शीर्षक पत्र कहता है कि भारत में देसी गायों के साथ विदेशी सांडों के मेल से विकसित संकर नस्ल की गाय में भी विशुद्ध ए2 बीटा-केसीन के गुण पाए जाते हैं। संकर किस्म की गायों में ए1 प्रोटीन की मौजूदगी दुर्लभ होने के साथ ही नदारद रहती है।

उभरता वैश्विक रुझान दूध को उसके बीटा-कैसीन की प्रकृति के आधार पर ए1 और ए2 श्रेणियों में वर्गीकरण का है। कुल दुग्ध प्रोटीन में बीटा-केसीन की मात्रा 30-35 फीसदी होती है। ए2 दूध को आम तौर पर ए1 पर वरीयता दी जाती है क्योंकि यह मां के दूध से मेल खाता है। भारतीय नस्ल वाली गाय का दूध भी इसी श्रेणी से संबंधित है।

एनएएएस का रणनीति पत्र 1,500 पशुओं के तुलनात्मक विश्लेषण के नतीजों पर आधारित है। करनाल स्थित नैशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने इस अध्ययन के दौरान संकर किस्म की गायों को भी शामिल किया था। अध्ययन से पता चला कि भारत के 91 फीसदी देसी मवेशियों के दूध में केवल ए2 बीटा-केसीन ही होता है। बमुश्किल 0.09 फीसदी नमूनों में ही ए1 बीटा-केसीन के नाममात्र के निशान पाए गए। खास बात यह है कि किसी भी भारतीय मवेशी का दूध ए1 किस्म का नहीं था। ए1 एवं ए2 किस्म के दूध के गुण एवं दोष के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका जैसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में भी लोग ए1 दूध को लेकर फिक्रमंद हो रहे हैं। न्यूज़ीलैंड ने तो प्रजनन में इस्तेमाल होने वाले सांडों को ए1 एवं ए2 के तौर पर चिह्नित करना शुरू कर दिया है ताकि ए2 दूध देने वाली गायों को बढ़ावा मिले। ए2 कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम का एक कारोबारी घराना ए2 किस्म की गायों की पहचान एवं उनके दूध की बिक्री के लिए आगे आया है। उसने 'ए2' और 'ए2 मिल्क' को अपने ट्रेडमार्क के तौर पर पंजीकृत करा लिया है। बहरहाल एनएएएस का यह रणनीतिक पत्र कहता है कि ए2 दूध के उत्पादन में भारत को यूरोप के दुग्ध उत्पादक देशों की तुलना में बढ़त हासिल है। ऐसी स्थिति में भारत ए2 दूध को लेकर दुनिया भर में बढ़ती मांग को आसानी से पूरा कर सकता है।

सीएमपीडीआई में सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2019

रांची संवाददाता : 25 अक्टूबर। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में सीएमपीडीआई के सतर्कता विभाग के तत्वावधान में बिरसा सी उच्च विद्यालय, हथिया गोंदा, कांके रोड, रांची तथा डीएवी हेहल जूनियर विंग में ''ईमानदारी-एक जीवनशैली'' विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिरसा उच्च विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में लगभग 20 छात्र/छात्राओं ने भाग लिया । इस मौके पर सीएमपीडी आई के महाप्रबंधक पुष्कर ने डीएवी हेहल जूनियर विंग विद्यालय में आयोजित भाषणप्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागी प्रथम-ऋषिकाचौधरी, द्वितीय-अनन्या श्रीवास्तव एवं तृतीय स्थान पर रही प्रियांशी को पुरस्कृत किया जब कि बिरसा उच्च विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागी प्रथम-मंटुमंडल, द्वितीय-रूचिकुमारी एवंतृतीय स्थान पर रहीं खूशबु परवीन को सीएमपीडीआई के मुख्य प्रबंधक (सतर्कता) आलोक कुमार त्रिपाठी एवंमुख्य प्रबंधक एस0 के0 ठाकुर ने पुरस्कृत किया।

इस मौके पर सतर्कता विभाग, सीएमपीडीआई की ओर से वरीय प्रबंधक (वित्त) श्री एस0बी0 तिवारी एवं सहायक प्रबंधक श्रीमती ऋतु सिंह एव बिरसा उच्च विद्यालय की ओर से श्रीमती सुषमा तिवारी, एस0डी0पी. सिंह तथा डीएवी हेहल जूनियर विंग की ओर से शिक्षक/शिक्षिकागण पी0एस0 दास, श्रीमती शीला रमेश एवं डॉ0 अर्चना तिवारी उपस्थित थीं।

विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन जरूरी

धनतेरस के दिन झारखंड में 1495 सौ करोड़ रूपये से अधिक की बिक्री हुयी। और सिर्फ रांची में ही साढे चार सौ करोड़ की खरीददारी लोगों ने की। ये सब देश में लोगों के जीवन स्तर के उठने का सूचक है। इन सब के बीच बड़ी खबर है कि राज्य में सिर्फ धनतेरस के दिन ही पचास हजार दो पहिया वाहनों की संख्या बढ़ गयी। इसमें चारपहिया वाहनों की संख्या नहीं जोड़ी गयी है। यह लाजमी है कि जरूरतों और शौक के लिये लोग सुख सुविधा की चीजें खरीदेंगे। इन सब के बीच हमें यह भी देखना होगा कि विकास के नाम पर हम उन चीजों का सुतंलित उपयोग करें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। एक दिन में ही सड़कों पर पचास हजार नये वाहनों का आ जाना अगर पर्यावरण और प्रदूषण के लिहाज से देखें तो कोई सुखद स्थिति नहीं है। ध्वनि प्रदूषण से लेकर, वायू प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या बढाने के लिये ये पचास हजार वाहन खाद पानी का ही काम करेंगे। हमारा देश एक धार्मिक और उत्सवजीवी देश है। यहां ऋतुओं और समय के हिसाब से पर्व त्यौहार बनाये गये हैं। और गौर से देखने पर यह पता चलता है कि ये सभी प्रकृति के अनुकूल बने हुये हैं। लेकिन हमने इन उत्सवों के मूल संदेश को पीछे छोड़ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उत्सवों में बदल दिया है। सरकार को दीपावली में कम पटाखे छोड़ने का आग्रह करना पड़ रहा है। दिल्ली में दीपावली के बाद कई दिनों तक धुंध छायी रहती है और अकेले दीपावली के दिन छोड़े गये पटाखों के कारण वहां का आकाश जितना प्रदूषित हो जाता है, उतना आम दिनों के महिनों भर में भी नहीं होता। अब ए सी आम भारतीयों के घरों में भी दिखता है, जो भारी मात्रा में क्लोरोफ्लोरो का उत्सर्जन करता है। इससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचा है। क्या ए सी हम आम भारतीयों के लिये सचमुच जरूरी चीज है? इसपर विचार करना होगा। विकास रफ्तार के बढने पर वाहनों से लेकर सुख सुविधा के चीजों की संख्या भी बढेंगी ही, लेकिन इसका संतुलन के साथ उपयोग भी बहुत जरूरी है, हम आज भी मामूली दूरी के लिये वाहनों का उपयोग करते हैं। अकेले आने जाने के लिये भी चारपहिया वाहन से चलते हैं, कार शेयरिंग हमारे शान के खिलाफ लगता है और ए सी जैसे उपकरण हम रसूख दिखाने के लिये भी लगाये रखते हैं। ये देश के विशाल मध्यवर्ग की चिंता होनी चाहिये कि हम विकास करने के साथ ही पर्व त्यौहारों को इस तरह से मनाये कि पर्यावरण भी बचा रहे।

> अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे पर्व त्यौहार प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षक हैं, लेकिन हमने आधुनिकता के दौर में इन्हें शोरगुल और प्रदूषण फैलाने का आयोजन बना लिया। दीपावली पर तेल के दिये जलाने से जहां वर्षा ऋतु में जन्में असंख्य कीट पतंगो की संख्या पर नियंत्रण होता है वहीं छठ महापर्व के बहाने ही तालाबों, नदियों की और उसके किनारों की साफ सफाई हो जाती है, अन्यथा हम सब तो इन्हें सालो भर प्रदूषित करते रहते हैं।

भोपाल में काटे जा रहे हैं पेड़

भोपाल के न्यू मार्केट से सटे टीटी नगर इलाके में प्रवेश करते ही धूप में पेड़ों के सूखते पत्तों की महक आने लगती है। पास जाने पर दिखता है कि कहीं पेड़ों की कटी हुई शाखाएं बिखरी हैं तो कहीं मोटा तना कटा हुआ पड़ा है। निर्माण कार्य में लगे मजदूर कभी कटे हुए तनों पर आराम फरमा रहे हैं तो कभी आसपास बिखरे कटे हुए तने, शाखाओं और उनके मुरझाए पत्तों को समेटकर ट्रॉली में रख रहे हैं। पेड़ों के कटने के बाद जमीन में हुए बड़े गड्ढे विनाश के इस मंजर को दिखा रहे हैं। यह विनाश स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भोपाल को विकसित किए जाने की वजह से हो रहा है।सिर्फ स्मार्ट सिटी ही नहीं, भोपाल में चल रहे दूसरे विकास कार्यों के लिए भी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही है। विधायक आवास बनाने की पुरानी योजना को अमल में लाने के लिए 1000 पेड़ों की बली दी जा रही है। यह काम इतनी सतर्कता में किया जा रहा है कि अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। वहीं शहर में बीआरटीएस कॉरिडोर के लिए 2400 पेड़ काटे गए थे। नर्मदा पेय जल स्टोरेज के लिए 400, शौर्य स्मारक के लिए 200, सिंगार चोली ब्रिज और सड़क चौड़ीकरण के लिए 1000, हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर विकास कार्य के लिए एक हजार से अधिक और एयरपोर्ट रोड के लिए दो हजार से अधिक पेड़ बीते कुछ महीनों में काटे गए हैं। मुंबई में आरे वन क्षेत्र को काटने से रोकने के लिए भोपाल के लोगों ने भी अपनी आवाज बुलंद की थी, लेकिन शहर में हो रहे पेड़ों की कटाई का कोई विरोध होता नहीं दिख रहा है।

बेशकीमती पेड़ काटे, इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी तबाह हुई

शहर के पर्यावरणविद् सुभाष पांडे बताते हैं कि उन्होंने हाल ही में एक शोध में पाया कि भोपाल में बीते 10 साल में 26 प्रतिशत हरियाली में कमी आई है। सुभाष बताते हैं कि विकास कार्य के दौरान पेड़ तो काटे जा रहे हैं लेकिन उतनी गंभीरता के साथ उसकी भारपाई नहीं हो रही है। उनका मानना है कि 50 से 100 साल पुराने पड़ काटकर उसके बदले नए पेड़ लगाने से पर्यावरण को हुए नुकसान की भारपाई हो भी नहीं सकती है।

अब भी 19वीं सदी में अटके जल-उपयोग कानून

मिहिर शाह

> लोकप्रिय मगर गलत समझा गया नजरिया यह है कि पानी को केंद्रीय विषय बनाने से भारत के जल संसाधन का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। इसकी अहमियत बता रहे हैं *मिहिर शाह*

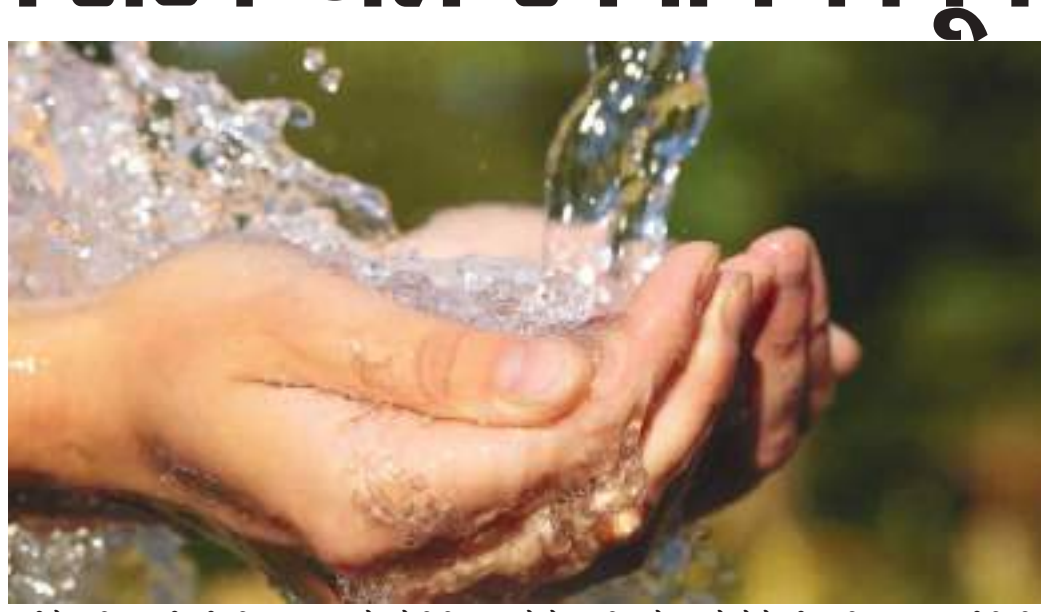

केंद्र सरकार की तरफ से भारत में पानी संबंधित कानूनों में तत्काल सुधार के लिए गठित समिति की मैंने वर्ष 2015 में अध्यक्षता की थी। भारतीय संविधान में पानी को राज्य का विषय बनाया गया है। भारत में यह धारणा काफी लोकप्रिय रही है कि पानी को केंद्रीय सूची का विषय बनाने से राष्ट्रीय जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा लेकिन यह दोषपूर्ण नजरिया है। हमारी समिति ने इससे अलग रुख अपनाया। एक साझा एवं समान संसाधन के तौर पर पानी की अलग प्रकृति को देखते हुए और जल प्रबंधन की सभी सफल कोशिशों के आधार पर हमने आनुषंगिकता का सिद्धांत अपनाने की वकालत की जिसमें समाधान को समस्या के बेहद करीबी स्तर पर लाने की जरूरत होती है। लिहाजा जल प्रबंधन को हरसंभव स्तर तक विकेंद्रीकृत करने की जरूरत है, जल विवादों के समाधान में प्राथमिक हितधारकों को शामिल किया जाए और संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन में रेखांकित बिंदुओं को भी ध्यान में रखा जाए।

हालांकि उसी समय हमने यह भी माना कि हर दिन पानी को लेकर संघर्ष बढने और सघन होने से साझा रवैये और सिद्धांतों के बारे में एक व्यापक राष्ट्रीय मसौदा बनाने की फौरी जरूरत है ताकि पानी का विवेकपूर्ण एवं सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण इस्तेमाल किया जा सके। इसी के साथ संदर्भ-आधारित विवरण में लचीलेपन की भी गुंजाइश रखनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रीय हित में वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। इस तरह समिति ने राष्ट्रीय जल प्रारूप कानून (एनडब्ल्यूएफएल) का एक मसौदा तैयार किया। हमने बेहद सावधानी से यह प्रस्ताव रखा था कि एनडब्ल्यूएफएल को संविधान के अनुच्छेद 252(1) के तहत विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसके मुताबिक दो या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इस तरह का कानून पारित कराने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती हैं। यह एक प्रारूप कानून है और इसका मकसद जल प्रबंधन को केंद्रीकृत करना या पानी को लेकर संवैधानिक स्थिति बदलना नहीं है। इसके स्थान पर यह कानून पानी के संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन के सिद्धांतों का एक व्यापक राष्ट्रीय विधिक ढांचा मुहैया कराता है। यह केंद्र, राज्य एवं स्थानीय शासन निकायों द्वारा विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग को नियमित करेगा।

एनडब्ल्यूएफएल एक ऐसा नजरिया अपनाने पर जोर देता है जिसमें आम जनजीवन में पानी को केंद्रीय एवं बहुआयामी जगह दी गई है। यह कहता है, 'पानी भारत के लोगों की साझा विरासत है, अपने सभी रूपों में जीवन के वजूद के लिए आवश्यक है, पारिस्थितिकी प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है, आजीविका के लिए बुनियादी जरूरत है, सफाई का एक एजेंट है, कृषि और उद्योग एवं वाणिज्य जैसी आर्थिक गतिविधियों का जरूरी अंग है, परिवहन एवं मौजमस्ती का एक साधन है, जनसमूह, समाज, इतिहास एवं संस्कृति का अविभाज्य अंग है, और कई संस्कृतियों में कुछ हद तक दैवीय मान्यता होने से इसे पवित्र भी माना जाता है।' अमूमन ऐसी सोच नदारद रही है लेकिन भारत में जल नीति एवं कार्यक्रमों का खाका तैयार करते समय इसे मार्गदर्शक माना जाना चाहिए। यह कानून उच्चतम न्यायालय द्वारा पानी के बारे में दिए गए सभी अहम फैसलों को समाहित किए हुए है, जैसे कि सार्वजनिक न्यासिता का सिद्धांत और पानी के अधिकार की स्वीकृति। उच्चतम न्यायालय कह चुका है कि 'हमारी विधिक प्रणाली में सार्वजनिक न्यासिता सिद्धांत भी अधिकार-क्षेत्र का हिस्सा है। राज्य लोक-उपयोग एवं मनोरंजन के निमित्त सभी प्राकृतिक संसाधनों का न्यासी है।' सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि पानी इंसानों के वजूद के लिए बुनियादी जरूरत है और अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार एवं मानवाधिकार का हिस्सा है। इस तरह एनडब्ल्यूएफएल के मुताबिक, पानी भारत के लोगों की साझा विरासत है, जल एवं सभी संबद्ध पारिस्थितिकियों के संरक्षण के लिए सार्वजनिक न्यास में निहित और सबके लिए तर्कपूर्ण निषेधों का विषय है। इसके अलावा राज्य पानी का सभी स्तरों पर जनता का सार्वजनिक न्यास है और सबके फायदे के लिए एक न्यासी के रूप में पानी को संरक्षित के प्रति आबद्ध है।

नतीजतन, एनडब्ल्यूएफएल पानी का मुद्दा 21वीं सदी में लेकर आता है जो पानी के बारे में उभरती वास्तविकता, समझ एवं नजरिये को परिलक्षित करता है। विश्वास करना मुश्किल हो सकता है लेकिन हमारा भूजल अब भी 19वीं सदी में बने ब्रिटिश कानूनों से संचालित होता है जिनके प्रावधान जल उपलब्धता में असमानता बढ़ाने और जल उपयोग में असंवहनीयता बढ़ाते हैं। पूर्ण प्रभुत्व का सिद्धांत भूस्वामियों को यह अधिकार देता है कि उनकी जमीन के नीचे का समूचा पानी उनका है। भूजल की कानूनी स्थिति जमीन की चल संपत्ति के बारे में कुछ ऐसी है: जमीन का स्वामित्व रखने वाले लोग उसकी खुदाई कर सकते हैं और अगर खुदाई के क्रम में वह अपने पड़ोसी के कुएं में जमा पानी को बिखेर देता है तो यह कृत्य चोट-रहित नुकसान के दायरे में ही आता है और उस आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब इसे जल-विज्ञान के जरिये अधिक बेहतर ढंग से समझा जा सकता है कि किसी भी भूखंड के नीचे मौजूद पानी को रिचार्ज के तौर पर नहीं निकाला जा सकता है। अधिकांश जलाशयों के रिचार्ज क्षेत्र उस जलभंडार स्थल का केवल एक हिस्सा भर होता है। इस तरह कई मामलों में किसी भी जमीन के नीचे बह रहे पानी को थोड़ा दूर स्थित जमीन से एक जलाशय को रिचार्ज करना होगा। जब कई लोग एक ही समय पर भूमिगत जल का दोहन करते हैं तो पंपिंग के अलग केंद्रों के बीच जटिल व्यवधान की स्थिति पैदा होने लगती है।

भारत में यह बात काफी आम है क्योंकि यहां पर कुएं एक-दूसरे के काफी करीब स्थित हैं। जलस्तर में गिरावट इसी तरह आई है और इसके दुष्परिणामों के खिलाफ कोई विधिक संरक्षण उपलब्ध नहीं होने से करोड़ों लोगों की जिंदगी एवं आजीविका खतरे में पड़ गई है। इसीलिए हमारी समिति ने मॉडल भूजल संरक्षण प्रबंधन विधेयक 2016 का भी मसौदा तैयार किया था जिसमें एनडब्ल्यूएफएल के सिद्धांतों का ही इस्तेमाल किया गया है। यह तर्कसंगत उपयोग के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से भूजल का इस्तेमाल कर रहा है कि दूसरे लोग पानी के अधिकार से वंचित हो जाते हैं तो उसे गैरकानूनी माना जाएगा। इन कानूनी सुधारों एवं उपायों के बगैर हम पानी की अहमियत को लेकर किए गए बेहतरीन प्रयासों को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह नया कानूनी परिप्रेक्ष्य भारत में जल प्रबंधन की दिशा में नवाचार लाने का आधार साबित हुआ है।

लेखक शिव नाडर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं

घटने वन और बिगड़ता पर्यावरण

अभिजीत मोहन

विकास के लिए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का दोहन आवश्यक है। लेकिन इसकी सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए, जिसका कि पालन नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर जंगलों को उजाड़ने का ही नतीजा है कि आज मनुष्य को बढ़ते वैश्विक तापमान, ओजोन परत के क्षरण, भूकम्प, भारी वर्षा, बाढ़ और सूखे जैसी विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। घटने वन, बिगड़ता पर्यावरणवन किसी भी राष्ट्र की अमूल्य निधि होते हैं, जो वहां की जलवायु, भूमि की बनावट, वर्षा, जनसंख्या के घनत्व, कृषि और उद्योग आदि को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। भारत प्राकृतिक वन संपदा की दृष्टि से एक संपन्न देश रहा है। भारत में पौधों और वृक्षों की सैंतालीस हजार प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन वनों की कटाई के कारण प्रजातियां नष्ट हो रही हैं और जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं।

यह राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई की आरे कालोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। इस कालोनी में मेट्रो कारशेड के लिए ढाई हजार से ज्यादा पेड़ काटे जाने थे और वहां के निवासी और पर्यावरण संरक्षक इसका विरोध कर रहे थे। प्रशासन ने विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। तब मामला शीर्ष अदालत में पहुंचा। हालांकि तब तक दो हजार से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके थे। सरकार का तर्क है कि छोटे हिस्से से पेड़ काटे गए हैं। सरकार ने यह दलील भी दी कि इन पेड़ों को काटने से पहले तेईस हजार आठ सौ छियालीस पेड़ लगाए जा चुके हैं और पच्चीस हजार पौधे वृक्षारोपण के लिए बांटे गए हैं। लेकिन अदालत ने दो टूक कहा कि सवाल छोटे हिस्से का नहीं, बल्कि यह कानूनन गलत है तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

सर्वोच्च अदालत के पूर्व आदेश के अनुसार राज्यों को किसी क्षेत्र को जंगल के रुप में अधिसूचित करना आवश्यक है, लेकिन

महराष्ट्र सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। पर्यावरण संरक्षकों और विशेषज्ञों की मानें तो आरे को 'अवर्गीकृत जंगल' के रुप में समझा जाता था और वहां पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में पेड़ों की कटाई अवैध है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक यह अवर्गीकृत जंगल नहीं है और न ही यह संवेदनशील क्षेत्र है। सरकार ने पेड़ों की कटाई तब शुरू की थी जब बबई हाई कोर्ट ने आरे कालोनी को वन क्षेत्र घोषित करने और मुंबई नगर निगम की मेट्रो कारशेड के लिए पेड़ों की कटाई की इजाजत देने वाली अधिसूचना रद्द करने की मांग ठुकरा दी थी।

आज जिस तरह वनों को उजाड़ा जा रहा है, उससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। पिछले साल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने दावा किया था कि अगर जंगलों को बचाने की पहल तेज नहीं हुई तो 2025 तक देश के अन्य हिस्सों के साथ-साथ पूर्वोत्तर के छह राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का वन क्षेत्र खत्म हो जाएगा, जो आकार में मॉरीशस के कुल क्षेत्रफल के बराबर बैठता है। इन राज्यों में 2005 से 2013 के बीच वन क्षेत्र में 0.3 प्रतिशत की दर से कमी दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों ने इन्हीं राज्यों के घटते वन क्षेत्र को 2025 के वन क्षेत्र के अनुमान के लिए आधार बनाया है और उनका यह शोध पिछले दिनों 'अर्थ सिस्टम साइंस' नामक जर्नल में छपा है। चूंकि यह शोध हैदराबाद स्थित इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और तिरुवनंतपुरम स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने किया है, इसलिए शोध की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों का दावा है कि एक सौ तैंतीस साल में चालीस प्रतिशत वन क्षेत्र कम हो चुका है। वर्ष 1880 में देश में 10.42 लाख वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल होने का अनुमान लगाया गया था, जो देश के 37.1 प्रतिशत भौगोलिक हिस्से को दर्शाता था। लेकिन विकास के नाम पर वनों की अंधाधुंध कटाई की वजह से 1880 से 2013 के बीच इसमें चालीस प्रतिशत की कमी आई है। वन क्षेत्र में आ रही कमी के बारे में अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर पर लैंड चेंज मॉडलर सॉफ्टवेयर पर प्राचीन भारत के वन क्षेत्र का मॉडल तैयार किया है। इनमें उन इलाकों का पर्यवेक्षण किया गया है, जहां वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी हो रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर- पूर्वी राज्यों में गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा अधिकांश वन क्षेत्र की भूमि को लीज पर लेने और बड़े स्तर पर वन क्षेत्रों को कृषि के लिए उपयोग में लाने के कारण वन क्षेत्र में लगातार गिरावट आ रही है। तथ्य यह भी कि अंधाधुंध विकास के नाम पर मानव प्रति वर्ष सात करोड़ हेक्टेयर वनों का विनाश कर रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले सैकड़ों सालों में हमने प्रकृति की एक तिहाई से अधिक प्रजातियां नष्ट कर डाली हैं। जंगली जीवों की संख्या में भी पचास प्रतिशत की कमी आई है। यह स्थिति तब है जब वनों को बचाने के लिए 1950 से लगातार हर वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसके जरिए खेतों की मेड़ों, नदियों, नहरों और सड़कों के किनारे तथा बेकार भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है। वन-विकास कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने 1952 में ही वन-नीति बना ली थी और वन विकास के लिए नई-नई घोषणाओं के साथ वनों का क्षेत्र बाईस प्रतिशत से बढ़ा कर तैंतीस प्रतिशत करने के संकल्प व्यक्त किया था। इसके अलावा वनों पर सरकारी नियंत्रण रखने और वृक्षों की हरित पट्टी विकसित करने के कार्यक्रम भी तय किए। यही नहीं, वनों को बचाने के लिए 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना भी की गई थी। इस आयोग का कार्य वनों से संबंधित आंकड़े और सूचनाएं एकत्रित करना और उन्हें प्रकाशित करना है। लेकिन विडंबना है कि इस कवायद के बावजूद वनों का क्षेत्रफल बढ़ने के बजाए उसमें लगातार घटता ही जा रहा है। स्थिति यह है कि आज देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के महज 20.64 प्रतिशत हिस्से पर ही वन क्षेत्र रह गया है। अगर समय रहते वनों को संरक्षित नहीं किया गया तो न केवल लकड़ी, उद्योगों के लिए कच्चा माल, पशुओं के लिए चारा, औषधियां, सुगंधित तेल का संकट उत्पन होगा, बल्कि पर्यावरण भी तेजी से प्रदूषित होगा।

क्या इसलिये घट रहे हैं भारत में गधे?

देश में गधों की संख्या कम हो रही है। इसकी वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन संदेह जताया जा रहा है कि भारत में गधे का मीट खाया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पशुओं की आबादी पर जारी आंकड़ों में पाया गया है कि 2012 के मुकाबले 2019 में गधों की संख्या में 61.23 फीसदी की गिरावट आई है। घोड़े और गधों पर काम करने वाली संस्था ब्रूक का कहना है कि इन आंकड़ों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इससे लगता है कि गधों को मारा जा रहा है।

लाइवस्टॉक सेंसस 2019 के मुताबिक, 2012 में देश में गधों की संख्या 3.20 लाख थी, जो अब 1.20 लाख रह गई है। जबकि 2007 में गधों की संख्या 4.4 लाख थी। यानी कि 10 साल में देश में गधों की संख्या में लगभग एक चौथाई कमी आई है।

2012 से 2019 के बीच गधों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट राजस्थान व उत्तर प्रदेश में हुई है। राजस्थान में 2012 में गधों की संख्या 81 हजार थी, जो 2019 में घटकर 23 हजार रह गई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में पहले 57 हजार गधे थे, जो अब 16 हजार रह गए हैं। महाराष्ट्र में पहले 29 हजार गधे थे, अब 18 हजार हैं। गुजरात में 39 हजार से घटकर 11 हजार रह गए। बिहार में 21 हजार से घटकर 11 हजार रह गए। जम्मू कश्मीर में 17 हजार से घटकर 10 हजार, कर्नाटक में 16 हजार से घटकर 9 हजार, मध्य प्रदेश में 15 हजार से घटकर 8 हजार, हिमाचल प्रदेश में 7 हजार से घटकर 5 हजार, आंध्र प्रदेश में 10 हजार से घटकर 5 हजार गधे पाए गए।

सिंगल यूज प्लासिटक से बनाये प्रोडक्ट

वैज्ञानिकों ने सिंगल यूज प्लास्टिक से तरल उत्पाद, जैसे मोटर तेल, लुब्रिकेंट, डिटर्जेंट और यहां तक कि सौंदर्य प्रसाधन में बदलने की एक नई विधि विकसित की है। यह खोज वर्तमान रीसाइक्लिंग के तरीकों में भी सुधार लाएगी। यह उत्प्रेरक नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, अमेरिका, नेशनल लेबोरेटरी एंड एमएस लेबोरेटरी की टीमों ने तैयार की है। यह अध्ययन एसीएस सेंट्रल साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन टीम के सदस्य नॉर्थ वेस्टर्न के केनेथ आर. पोपेलमीयर ने कहा कि इस विधि से प्लास्टिक को इस तरह से विकसित किया जाएगा कि वे पर्यावरण और इंसान को कम से कम नुकसान पहुंचाए। हर साल दुनिया भर में 38 करोड़ टन प्लास्टिक बनाया जाता है और बाजार में प्लास्टिक की वृद्धि लगातार जारी है।

दूध उत्पादन में कायम रहेगा दुनिया में भारत का दबदबा

वैश्विक दूध बाजार में भारत रहेगा आगे!

संजीव मुखर्जी

बिजनेस स्टैंडर्ड दूध उत्पादन में कायम रहेगा भारत का दबदबादूध उत्पादन के लिहाज से वैश्विक दूध बाजार में भारत का वर्चस्व आगे भी बरकरार रह सकता है क्योंकि ताजा आंकड़े में संकर एवं देसी दोनों नस्लों के दुधारू मवेशियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आज जारी 20वीं मवेशी गणना के अनुसार देश में गोवंश की कुल संख्या में मामूली इजाफा हुआ है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या घट रही थी। लेकिन 2012 से 2019 के दौरान देसी नस्ल के गोवंश की संख्या में गिरावट चकित करने वाली रही। 2019 में देश में गोवंश की संख्या 19.24 करोड़ थी, जो 2012 की गणना से करीब 0.8 फीसदी अधिक है। 2012 में गोवंश की कुल संख्या 2007 के 19.90 करोड़ से घटकर 19.09 करोड़ रह गई थी। गोवंश की संख्या में बढ़ोतरी मुख्य रूप से संकर नस्ल की मवेशियों की संख्या बढ़ने की वजह से हुई है। संकर नस्ल की गायें ज्यादा दूध देती हैं इसलिए किसान इसे पालना पसंद करते हैं। संकर नस्ल की मादा की संख्या 2012 के 3.37 करोड़ से 30 फीसदी बढ़कर 2019 में 4.69 करोड़ से अधिक हो गई, वहीं देसी मादा गायों की संख्या 10 फीसदी बढ़कर 2019 में 9.81 करोड़ पहुंच गई। हालांकि देसी नस्ल के मवेशियों की कुल संख्या 2019 में 2012 की तुलना में कम हुई है लेकिन देसी मादा मवेशियों की संख्या

खासी बढ़ी है। 2012 से 2019 के दौरान दुधारू मवेशियों की कुल संख्या 6 फीसदी बढ़ी है।बिजनेस स्टैंडर्ड दूध उत्पादन में कायम रहेगा भारत का दबदबासंकर मवेशियों ने 2018-19 में भारत में कुल 18.8 करोड़ टन दुग्ध उत्पादन में लगभग 28 फीसदी का योगदान दिया। 20वीं मवेशी गणना के अनुसार भैंस की संख्या भी बढ़कर 10.98 करोड़ हो गई, जो वर्ष 2012 में 10.87 करोड़ थी।

एनडीडीबी और जीसीएमएमएफ के साथ काम कर चुके वरिष्ठ डेरी सलाहकार डॉ. आर एस खन्ना ने कहा, 'हालिया मवेशी गणना से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि सूखे और कीमतें गिरने के बावजूद क्यों पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में दुग्ध उत्पादन 6 फीसदी से अधिक रफ्तार से बढ़ा है।' कुल मिलाकर, आंकड़ों से पता चलता है कि मवेशियों की कुल संख्या 2019 में बढ़कर 53.57 करोड़ हो गई है, जो वर्ष 2012 में 51.20 करोड़ थी। इस बढ़ोतरी में भेड़ और बकरी की संख्या का खासा योगदान रहा है।

दुर्लभ बीमारियों का इलाज और पहचान होगी आसान

एक नई परियोजना के तहत देश के विभिन्न समुदाय के लोगों की संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा शुरू की गई इस पहल के अंतर्गत 1008 लोगों के जीनोम का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग दुर्लभ आनुवांशिक बीमारियों के निदान, कैंसर जैसी जटिल बीमारियों के उपचार, नई दवाओं के विकास और विवाह पूर्व भावी जोड़ों के अनुवांशिक परीक्षण में किया जा सकता है।

इंडिजेन नामक यह परियोजना इस वर्ष अप्रैल में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएस-ाआईआर) द्वारा शुरू की गई थी। इस परियोजना का संचालन सीएसआ-ईआर से संम्बद्ध जीनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली एवं कोशकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र, हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने किया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने इस परियोजना के बारे में बताते हुए कहा कि ''प्रिसिजन मेडिसिन के उभरते क्षेत्र में तकनीकी जानकारी, आधारभूत आंकड़ों और घरेलू क्षमता के विकास में संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग महत्वपूर्ण हो सकती है।यह पहल बीमारियों की सटीक एवं त्वरित पहचानव उपचार के लिएआनुवांशि-ाक लक्षणों तथा संवेदनशीलता आदि का निर्धारण करने में बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।

ओंकारेश्वर बांधः जल सत्याग्रह शुरू

नर्मदा बचाओ आंदोलन की अपील पर डूब प्रभावितों का पुनर्वास किए बगैर ओंकारेश्वर बांध में भरे जा रहे पानी के विरोध में आज शुक्रवार से सैकड़ों की संख्या में डूब प्रभावितों ने कामनखेड़ा गांव (खंडवा जिला, मध्य प्रदेश) में जल सत्याग्रह शुरु किया। यह सत्याग्रह सुबह 11 बजे शुरू हुआ। यह जानकारी नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता आलोक अग्रवाल ने डाउन टू अर्थ को दी। उन्होंने बताया कि जल सत्याग्रह डूब प्रभावित ग्राम कामनखेड़ा में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। अग्रवाल ने बताया कि इस जल सत्याग्रह को लेकर हमने ग्राम घोघलगांव, टोकी, एखण्ड, कामनखेड़ा आदि ग्रामों में डूब प्रभावितों के साथ बैठक करके यह निर्णय लिया है। ध्यान रहे कि गत 21 अक्टूबर से ओंकारेश्वर बांध में जलस्तर बढ़ाते हुए एक मीटर से ज्यादा पानी भरा गया है। इससे कई गांवों के रास्ते बंद हो गए हैं। साथ ही सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पानी के बीच टापू बन गई है। अग्रवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ओंकारेश्वर बांध को पूरी क्षमता 196.6 मीटर तक भरने की तैयारी में है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के शिलान्यास व उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा

केंद्र और राज्य सरकार डबल रफ्तार से झारखंड के सतत विकास में जुटी

- मुख्यमंत्री ने 201 योजनाओं का शिलान्यास व 163 योजनाओं का शिलान्यास किया
- मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के तहत 1136 आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अम्बेडकर आवास योजना के तहत आवंटन पत्र प्रदान किया
- यह दिवाली गरीबों के लिए खुशियां लेकर आई है
- 25 साल रहने का प्रमाण दें और सरकार के लीजधारी बनेः सीएम

संवाददाता

बागुनहातु फुटबॉल मैदान, जमशेदपुरः केंद्र और राज्य सरकार डबल रफ्तार से झारखंड के विकास में जुटी है। हम सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ काम कर रहे हैं। झारखण्ड को ऊंचाइयों पर ले जाने का सिर्फ एक ही विकल्प है और वह है विकास तेजी से विकास। ये बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूर्वी सिंहभूम के बागुनहातु मैदान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास आवंटन एवं विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन कार्यक्रम में कही।

महिला शक्ति को राज्य की शक्ति बनाना है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास विभाग व खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के जरिए महिलाओं को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जा रहा है। महिलाएं रोजगार व स्वरोजगार से आच्छादित हो अपने आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर रहीं हैं। आज खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान किया गया। यह उनके आर्थिक उन्नयन में सहायक होगा। सखी मंडल के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। समय-समय पर सरकार उन्हें राशि उपलब्ध करा रोजगार व स्वरोजगार की ओर अग्रसर कर रही है। राज्य की महिला शक्ति को हमें और सशक्त बनाकर झारखण्ड की शक्ति बनाना है।

ग्राम उद्योग का जाल बिछाना है

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड संभावनाओं से भरा प्रदेश है। लेकिन यहां गरीबी है। सरकार छोटे-छोटे ग्राम उद्योग का जाल बिछाने की योजना पर कार्य कर रही है। यह गरीबी समाप्त करने में सहायक होगा। छोटे-छोटे उद्योग लगाकर लोग स्वावलंबी बन सकते हैं। सरकार हमेशा इनके साथ है और लगातार छोटे-छोटे उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य भी कर रही है।

पूर्वी क्षेत्र के लोगों को मिलेगी सुविधा

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस तरह टाटा स्टील के क्वार्टर में रहने वालों को सुविधा मिल रही है उस तरह जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र की बस्ती में रहने वालों को भी सुविधा मिलेगी। यहां के लोगों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए बात हो गई है। व्यवसायिक और रेजिडेंशियल एरिया में जल्द क्वार्टर की तरह बिजली उपलब्ध होगा। साथ ही जिस्को इन बस्तियों में पानी उपलब्ध कराएगा। अब टाटा की बिजली पूर्वी क्षेत्र की झुग्गी झोपड़ी और सरायकेला के बस्ती में भी घरों को रोशन करेगी।

25 साल से रहने का प्रमाण दें और सरकार के लिए धारी बने

मुख्यमंत्री ने कहा कि जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में रह रहे लोग 25 साल से रहने का प्रमाण पत्र सरकार को दें और सीधे सरकार के लीज धारी बनें, इससे पहले इस तरह का निर्णय किसी सरकार ने नहीं लिये था। अब तक 3 लोगों ने 30 साल का प्रमाण पत्र दिया है, उनका लीज स्वीकृत हो गया है।

योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है

सांसद श्री विद्युतवरण महतो ने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में लगातार इस तरह का आयोजन हो रहा है। राज्य गठन के बाद इन 5 वर्षों में हमने लंबा सफर तय किया। 5 वर्ष में हमने विकास के कई काम किये हैं। सरकार प्रदेश के विकास में जुटी है। आज गरीब की योजना उन तक पहुंच रही। बिचौलिओं की भूमिका अब समाप्त हो गई है। पैसा गरीबों के खाते में मिल रहा है। उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत योजना समेत अन्य योजनाओं से राज्य के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आगे हमें और भी बहुत कुछ करना है।

कृषि उत्पादों के मूल्यवर्द्धन

.....पेज 1 का शेष

उत्पाद जैसे-मडुआ आटा , मडुआ लड्डू , मडुआ हलवा , मडुआ पौष्टिक रोटी , मडुआ केक , रागी कूकीज, रागी पास्ता , रागी सेवई एवं मल्टी ग्रेन रागी बिस्कुट के अलावा मशरुम से मशरुम आचार , आंवला से आंवला आचार, आंवला कैंडी एवं आंवला मुरब्बा, कटहल से कटहल आचार तथा टमाटर से टोमेटो सॉस को वैज्ञानिक तरीके से तैयार करने की व्यावहारिक बारीकियों एवं तकनीकों को बताया। व्यावहारिक ट्रेनिंग के बाद सभी छात्रों ने कृषि उत्पादो में मडुआ से रागी कूकीज, रागी पास्ता , रागी बटर केक , रागी सेवई एवं मल्टी ग्रेन रागी बिस्कुट , मशरुम से मशरुम आचार, आंवला से आंवला आचार, आंवला कैंडी एवं आंवला मुरब्बा, कटहल से कटहल आचार तथा टमाटर से टोमेटो सॉस का व्यावसायिक उत्पादन किया। इन उत्पादों का पैकेट तैयार करना और सभी उत्पादों की बाजार में बिक्री एवं विपणन प्रबंधन के अनुभवों को जाना। मडुआ (रागी), मशरुम, आंवला, कटहल और टमाटर के पोष्टिक और गुणकारी होने के कारण उनके उत्पादों की बाजार में ज्यादा मांग है। छात्रों ने अपने उत्पादों को विश्वविद्यालय के प्रागंण में ही बेचा। गुणवत्ता और उत्तम स्वाद की वजह से सभी उत्पादों को काफी पसंद किया गया। छात्रों ने रागी कूकीज (बिस्कुट) को 160/- रुपये प्रति किलो, रागी पास्ता 200/- रुपये प्रति किलो, रागी सेवई 200/- रुपये प्रति किलो, रागी बटर केक 200/- रुपये प्रति किलो, मशरुम आचार 360/- रुपये प्रति किलो, ओल आचार 250/- रुपये प्रति किलो, कटहल आचार 200/- रुपये प्रति किलो और टोमेटो सॉस 130/- रुपये प्रति किलो की निम्नतम दर पर बेचा। छात्रों ने सभी जरूरी संसाधन और उत्पादों की लागत और उत्पादों से लाभ और मुनाफा का भी आकलन किया और करीब 25-40 प्रतिशत तक का लाभ प्राप्त किया। उन्होंने इस तरह के व्यवसाय की शुरुआत के लिए उत्पादन ईकाई की स्थापना हेतु बैंक के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भी तैयार की।स्नातक छात्र विभांशु दिब्याल का कहना है कि बाजार मांग के अनुसार कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन से कई उत्पाद तैयार कर बढ़िया लाभ लिया जा सकता है। यह क्षेत्र कृषि स्नातकों को सफल उद्यमी बनाने में काफी सहायक होगा।स्नातक छात्रा पूजा कुमारी ने कहा कि ग्रामीण और शहरी महिलाएं प्रतिदिन 3-4 घंटे का समय देकर इसे कम लागत वाली स्वरोजगार के रूप में अपनाकर आमदनी का साधन बना सकती है। इसे स्वरोजगार के माध्यम से झारखण्ड राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्षा डॉ (श्रीमती) रेखा सिन्हा ने बताया कि इस क्षेत्र में इक्छुक किसान एवं महिलाओं के लिए विभाग में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाता है। स्वरोजगार के लिए इच्छुक ग्रामीण युवा- युवतियों के लिए डिप्लोमा कोर्स की भी शुरुआत की गई है। बीएयू कुलपति डॉ राम शंकर कुरील बताते है कि गृह विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक ने कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन कर कई लुभावने और पौष्टिक उत्पादों को विकसित किया है, जिसकी बाजार में काफी मांग है। बीएयू के कृषि संकाय ने कृषि विषय के छात्रों में स्वरोजगार की भावना विकसित करने और तकनीकी प्रसार को बढ़-ावा देने हेतु अनुभवीजन्य शिक्षा कार्यक्रमों के अधीन कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन तकनीक से जोड़ा है। इससे छात्रों को पेशेवर कृषि स्नातक और सफल उद्यमी बनाने को बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र में कृषकों और ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है। इसे अपनाकर कृषि उत्पादों से बेहतर आय लिया जा सकता है।

कुछ कृषि उत्पादों के गुण

रागी उत्पाद के गुण

रागी उत्पाद का सेवन करने से शरीर प्राकृतिक रूप से चिंता एवं तनाव से मुक्त हो जाता है और बेचैनी और नींद ना आने जैसी समस्याएं नहीं सताती हैं। रागी माइग्रेन होने की स्थिति में काफी प्रभावशाली सिद्ध होता है। यह हड्डियों का विकास में मददगार, वजन घटने में फायदेमंद , मधुमेह नियंत्रण में सहायक , एनीमिया को दूर करने और कोलेस्ट्रोल कम करने में सहायक, त्वचा को जवां रखने और शिशुओं के लिए उपयोगी है।

मशरूम उत्पाद के गुण

मशरूम में 92 % पानी, 4 % कार्बोहाइड्रेट, 2 % प्रोटीन और 1 % से कम वसा पाया जाता हैं।100 ग्राम मशरूम 22 कैलोरी प्रदान करते हैं और विटामिन बी के समृद्ध स्रोत और तांबा और फॉस्फोरस, जिंक और पोटेशियम का मध्यम स्रोत है।

आंवला उत्पाद के गुण

रोग प्रतिरोधक चमता बढाती हैं और विटामिन सी का बढ़िया स्रोत हैं कमधुमेह, बवासीर, नकसीर, खांसी बलगम , पेशाब की जलन और पथरी रोग के लिए लाभकारी है। लीवर को शक्ति, शरीर की विषाक्त को दूर करने, खून को साफ रखने, आखो की रोशनी और शरीर की त्वचा के लिए फायदेमंद होता है।

कटहल उत्पाद के गुण

कटहल के आहार स्टार्च और फाइबर के बढ़िया स्रोत है। इसमें 74% पानी, 23% कार्बोहाइड्रेट, 2% प्रोटीन, और 1% वसा मौजूद होता है। 100 ग्राम कटहल के हिस्सा 9।5 किलो कैलोरी प्रदान करता है। यह विटामिन बी 6 का एक समृद्ध स्रोत और इसमें विटामिन सी और पोटेशियम मध्यम स्तर होता हैं।

टमाटर उत्पाद के गुण

टमाटर खाने में स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक होते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस व विटामिन सी पाये जाते हैं। एसिडिटी की शिकायत को दूर करने में सहायक होता है।

घर के भितर भी प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे

सुभाष

तीन मिनट, एक मौत से आशय है कि देश में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में औसतन तीन मिनट में एक बच्चे की मौत हो जाती है। वायु प्रदूषण से बच्चों की मौत के मामले सबसे अधिक राजस्थान में हुए हैं। इसके बाद जहरीली हवा की वजह से बच्चों की सांस लेना हुआ मुश्किल में हमने बताया कि अनस जैसे कई बच्चे लगभग हर माह अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। तीसरी कड़ी में बताया गया कि तीन दशक के आंकड़ों के मुताबिक बच्चों की मौत की दूसरी बड़ी वजह निचले फेफडे.के संक्रमण होना रहा है।बताया गया कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चे अस्थमा का शिकार हो रहे हैं। बच्चे घर के भीतर हो रहे प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं।

जयुपर के जेके लोन अस्पताल में 4 वर्ष के विशाल का दाखिला 12 अक्तूबर को हुआ था। विशाल जयपुर से 79 किलोमीटर दूर दौसा जिले के सैथल गांव का रहने वाला है।अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि विशाल को अपनी उम्र के हिसाब से करीब 16 किलो का होना चाहिए, हालांकि वह 8 किलो का ही है। अपने वांछित वजन से बिल्कुल आधा। बेहद दुबला और कमजोर विशाल खसरा के बाद ब्रोंका-इटिस न्यूमोनिया यानी निचले फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित हुआ है। विशाल के पिता मजदूरी करते हैं और मां गृहणी है।

विशाल की देखरेख कर रहीं उनकी मां बताती हैं कि उनके घर में चूल्हे पर ही खाना पकता है। दो साल पहले उनके घर गैस कनेक्शन पहुंचा है। हालांकि, चूल्हे का खाना ही सबको पसंद है, इसलिए गैस पर खाना नहीं पकाया जाता। लकड़ियां और सूखी पत्तियां ही चूल्हे में इस्तेमाल की जाती हैं। घर में धुआं होता है, लेकिन वह कहती हैं कि स्वाद तो चूल्हे का ही है। यह स्वाद उनके बच्चे के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, लेकिन वे अनजान हैं। घर के भीतर धुएं की वजह से वायु प्रदूषण होने का अनुपात राजस्थान में सबसे ज्यादा है। राजस्थान में अब भी ज्यादातर घरों में गैस कनेक्शन नहीं है या फिर गैस आने के बावजूद उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है। सांस की बीमारी से जूझता विशाल एक उदाहरण है।

देश में सबसे ज्यादा घर के भीतर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण मौतें भी राजस्थान में ही होती हैं। ग्लोबल बर्डेन डिजीज, 2017 के आंकड़ों के मुताबिक प्रति लाख की आबादी में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की राजस्थान में जहां कुल 126.04 मौतें होती हैं। वहीं, अकेले घर के भीतर होने वाले प्रदूषण के कारण एक लाख की आबादी में 67.47 पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत हो जाती है।

धूल के साथ धुएं के विविध स्रोत और प्रदूषण कणों के साथ बच्चों में अपना दुष्प्रभाव छोड़ रहे हैं। घर के चूल्हे का धुआं हो या फिर त्यौहारों और खुशियों के मौके पर जलाए और दागे जाने वाले पटाखे से उठता धुंआ दोनों ही फेफड़ों में प्रदूषण पहुंचा रहा है। गर्भवती महिलाओं के भ्रूण में मौजूद बच्चों को या फिर सामान्य महिला वायु प्रदूषण लगातार बीमार बना रहा है। धूल या धुएं के प्रदूषण के कारण बच्चे गर्भ में ही बीमार बन रहे हैं। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की चिकित्सा करने वाली किरण गुलेरिया बताती हैं कि गर्भवती महिलाओं के बच्चों में इनडोर पॉल्यूशन का खतरा सर्वाधिक बना रहता है। अभी यह अध्ययन किया जा रहा है कि इसका वायु प्रदूषण का भ्रूण में मौजूद बच्चे पर क्या वास्तविक असर होता है? यह बात तो देखी गई है कि 28 दिन की उम्र से नीचे वाले यानी नवजात बच्चों से लेकर पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में आंतरिक विकास की प्रक्रिया को वायु प्रदूषण प्रभावित करता है। वहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसलवेनिया के पापुलेशन स्टडीज सेंटर एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी विभाग के आशीष

गुप्ता ने ठोस ईंधन के बाहरी कारक, लिंग और भारत में वयस्क श्वसन स्वास्थ्य विषय पर शोध किया है। यह शोध अगस्त, 2019 में प्रकाशित किया गया। इसमें बताया गया है कि क्रॉनिक ऑबस्ट्रक्टिव पलमॉनरी डिजीज (सीओपीडी) के कारण दुनिया में सर्वाधिक मौत होती है। सीओपीडी का अर्थ है कि फेफड़ों के वायु मार्ग का बाधित हो जाना। यह बीमारी धुएं के कारण होती है। शोध पत्र के मुताबिक उच्च आय वाले देशों में तंबाकू का धुआं सीओपीडी का प्रमुख कारक है। वहीं, लकड़ी, उपले, कोयला, चारकोल और फसल अवशेष को ईंधन के तौर पर घर में चूल्हे पर इस्तेमाल करना निम्न आय वाले देशों में सीओपीडी का प्रमुख कारण है। इसके अलावा बीते कुछ वर्षों से यह गौर किया गया है कि दीपावली के बाद अस्पतालों में सांस की तकलीफ बढ़ जाने के बाद बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करना पड़ता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के दौरान पटाखों को जलाने और दागने पर नियंत्रण का आदेश दिया था। इसके बाद जून, 2019 में पटाखों से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर एक अध्ययन प्रकाशित किया गया। इस शोध पत्र को महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के इंटरडिस्पलनरी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज और चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन की ओर से किया गया था। इसके प्रमुख शोधकर्ता आर शाह थे। शोध पत्र के मुताबिक ऐसे पटाखे जिनके नजदीक जाकर बच्चों को उसका इस्तेमाल करना पड़ता है वे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के दुष्प्रभाव को झेलते हैं। अध्ययन में स्नेक टेबलेट में सबसे ज्यादा पीएम 2.5 का प्रदूषण पाया गया। इसके बाद चटाई (गारलैंड), फिर पुलपुल, छुरछुरिया, चकरी और अनाज पीएम 2.5 का प्रदूषण पैदा करते हैं। इसके न सिर्फ तात्कालिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं बल्कि दीर्घ अवधि वाले फेफड़ों के संक्रमण भी परेशान कर सकते हैं। ●

बालाजी डेंटल केयर

Address
Shiv Bhawan,
Laah Kothi, Ratu
Road, Ranchi-5
Ph. 9006833759

.....पेज 1 का शेष

18 वर्ष में 13 लाख असंगठित

1 माह में 13 लाख असंगठित मजदूरों का निबंधन हुआ

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य गठन के बाद 13 लाख असंगठित मजदू-रों का निबंधन हुआ था। यह आंकड़ा 18 वर्ष का है। लेकिन वर्तमान सरकार ने असंगठित मजदूरों के निबंधन का काम शुरू किया। मात्र एक माह के अंदर 13 लाख असंगठित मजदूरों का निबंधन हुआ। अब यह संख्या बढ़कर 26 लाख हो गई है। छूटे हुए श्रमिक अपना निबंधन करा लें। साथ ही श्रम विभाग के अधिकारी भी घूम घूम कर ऐसे श्रमिकों का निबंधन करना सुनिश्चित करें। क्योंकि इन मजदूरों में आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित लोग हैं। यह विभाग गरीबों के कल्याण के लिए ही कार्य कर रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। सभी असंगठित मजदूरों को योजना का लाभ दें। उनके बच्चों को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाएं। ताकि उन्हें रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ा जा सके।

सरकार कुशल कामगार का वेतन देना चाहती है

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर कुशल कामगार बनाने का कार्य हो रहा है। उन्हें कुशल कामगार का वेतन सरकार देना चाहती है। असंगठित मजदूर भाई बहन अपना निबंधन जरूर कराएं और असंगठित कर्मकार बीमा योजना, अंत्येष्टि सहायता, कौशल उन्नयन योजना, चिकित्सा सहायता योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ जरुर लें। ताकि किसी तरह की अनहोनी होने पर आपके परिजनों को तत्काल दो लाख रुपए की राशि प्रदान की जा सके।

आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका के मानदेय में बढ़ोत्तरी की घोषणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी की सेविका व सहायिका बहनें बच्चों को संस्कार देने के काम करती हैं। इसलिए सरकार ने आंगनबाड़ी केन्द्रों की कुल 73074 सेविकाओं, सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 35292 आंगनबाड़ी सेविकाओं को 500 रुपये मानदेय की बढ़ोत्तरी की जा रही है। इसके तहत ₹ 5900 के बदले उन्हें ₹ 6400 दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 35,245 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 250 रुपये की वृद्धि की जा रही है। इसके तहत ₹ 2950 के बदले उन्हें ₹ 3200 दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 2537 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को 500 रुपये मानदेय की बढ़ोत्तरी की जा रही है। इसके तहत ₹ 4200 के बदले उन्हें ₹ 4700 दिये जायेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं और सहायिक-ाओं के मानदेय मानदेय में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी होती है। इस बढ़ोत्तरी का पूरा आर्थिक वहन राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को यह निदेश दिया है कि अगली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए प्रस्ताव रखे जाएं।

67 हजार लोगों को रोजगार देने में हम सफल हुए

मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग लगातार बेहतर कार्य कर रहा है। रोजगार मेला का आयोजन कर हम लोगों को नियोजित कर रहे हैं। अब तक 67 हजार से अधिक लोगों को श्रम विभाग ने रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार प्रदान किया है। आज भी हमने कई लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन सभी नवनियुक्त लोगों को शुभकामनाएं। आप ईमानदारी से कार्य करते हुए राज्य का मान हमेशा बढ़ाएं।

केंद्र व राज्य सरकार श्रीमिकों के उत्थान में जुटी है

नगर विकास मंत्री श्री सीपी सिंह ने कहा कि श्रीमिकों के लिए कई योजनाएं संचालित हैं। सब्जी बेचने वालों से लेकर भवन निर्माण विभाग से जुड़े तमाम श्रीमिकों को लाभ दिया जा रहा है। लाभ सभी को मिले यह सरकार का प्रयास है। आप सभी श्रमिक योजनाओं का लाभ लें। अगर यह आप से संभव नहीं है तो फार्म मेरे पास है आपकी सहायता मैं करुंगा। कौशल विकास योजना के तहत रोजगार भी श्रमिकों को दिया जा रहा है। केंद्र व राष्ट्र का श्रमिकों के उत्थान में जुटी है।

फोटो न्यूज

कांके डैम किनारे यह चट्टान कभी जाड़े में भी पानी में डूबा रहता था, इस साल भी यह बता रहा है कि डैम में पर्याप्त जलासंग्रह नही हुआ फोटो : उज्ज्वल

यह रातू रोड का हेहल तालाब है। कुछ साल पहले नगर विकास मंत्री सीपी सिंह और पार्षद अशोक यादव ने खुद इसके जीर्णोद्धार का उदघाटन किया था।

रामकृष्ण विद्या निकेतन में बच्चों को दिया पर्यावरण संदेश और दीपावली उपहार

संवाददाता

रांची : रामकृष्ण विद्या निकेतन में बच्चों व शिक्षकों के संग ग्रीन रिवोल्ट व स्मृति न्यूज़ की टीम ने दीपावली के मौके पर खुशियां बांटी। विद्यालय में बच्चों को मिठाईयां, फल एवं मिट्टी के दीयों का वितरण स्वामी विवेकानंद मिशन के सदस्य व्यवसायी आशीष अग्रवाल के माध्यम से करवाया गया। बच्चों को ग्रीन रिवॉल्ट की ओर से आवंला का पौधा वितरण किया गया, यह पौधा ग्रीन रिवोल्ट की पाठिका सारिका भूषण ने मुहैया करवाई, वह बताती है की इस अखबार में बहुत सारी जानकारियां छपी होती हैं, और आज इसकी विशेषता में इस कार्यक्रम के माध्यम से योगदान कर रही हूँ भले ही छोटे बच्चों के माध्यम से ही सही, इस धरा को हरित व खुबसूरत करने का भी मौका मिला।ग्रीन रिवोल्ट की ओर से टीम का नेतृत्व कर रहे शशिभूषण कुमार ने बच्चों को संदेश दिया कि अक्सर बच्चें पटाखों की होड़ में लग जाते हैं,उस मस्ती के साथ-साथ अपने पर्यावरण से सामंजस्य बना के चले ताकि हमारा वातावरण भी शुद्ध बना रहे और हमें अपनी उपस्थिति हर छोटे बड़े मौकों पर दर्ज करते रहना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे । इस तरह के दीपावली गिफ्ट पाकर बच्चे काफी खुश थे। विद्यालय की प्राचार्या विनीता कुमारी ने सबों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से उज्जवल कुमार ,सुमित कुमार रोहित ,अनिमेष मिश्रा की भूमिका सराहनीय रही।

हिम तेंदूए को बचाने के लिये नेपाल में किया गया सर्वे

एजेंसियां : हिम तेंदुए (पैंथेरा उनिया) को एक 'वल्नरबल प्रजाति' माना जाता है, जो अब करीब 4,000 की संख्या में ही बचे हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा को देखते हुए, इनके रहने वाली जगहों को संरक्षित घोषित किया गया है। तेंदुओं को बचाने की इसी कड़ी में कैम्ब्रिज वि-श्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नेपाल के दो संरक्षित क्षेत्रों में जहां हिम तेंदुए और मनुष्य साथ-साथ रहते है, वहां के 705 घरों के लोगों से एक प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्र की, इन संरक्षित क्षेत्रों में -सागरमाथा, और अन्नपूर्णा राष्ट्रीय उद्यान शामिल थे। यह अध्ययन प्लोस वन पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोग हिम तेंदुओं के बारे में क्या सोचते है, उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताया। लोग हिम तेंदुए को पालतू पशुओं के शिकारी के रूप में देखते थे। स्थानीय चरवाहे कभी-कभी अपने पशुओं के शिकार के प्रतिशोध के कारण हिम तेंदुओं को मार देते थे।दूसरी ओर लोग हिम तेंदुओं को उनकी संस्कृति का हिस्सा मानते थे, इसके अलावा इनसे लोगों को फायदा होता है जैसे-

कि पर्यटकों को यहां आकर्षित करना, जो सीधे- सीधे कमाई का एक जरिया है और तेंदुओं द्वारा जंगल में रह, रहें शाकाहारियों का शिकार करके इनकी संख्या को भी नियंत्रित करना है।अध्ययन में हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए स्थानीय तरीको का पता चला, जिसे संरक्षण उपायों के तहत अपनाया जा सकता है। इन उपायों में तेंदुओं की हत्या और उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाना, यदि तेंदुए द्वारा पशुओं का शिकार किया जाता है तो बदले में मुआवजा देने की योजनाएं, पर्यावरण से संबंधित शिक्षा और गतिविधियां शामिल हैं। इसके विपरीत, स्थानीय लोग संरक्षण उपायों के अधिक विरोधी थे, वे मानते हैं कि इन उपायों के लागू होने से उनकी आजीविका प्रभावित होगी, जैसे कि लकड़ी इकट्ठा करके यहां के लोग उसे बाजार में बेचते है, यह उनके आय का एक साधन है, इस पर पाबंदी लगना आदि। हिम तेंदुओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने वाले लोगों का मानना था कि, संरक्षण उपायों में मिलने वाले लाभों को बढ़ाया जाना चाहिए जैसे मुआवजा देना, संरक्षित क्षेत्रों को लोगों के लिए प्रतिबंधित करने के साथ-साथ वहां रहने वाले स्थानीय लोगों की आजीविका की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। तेंदुए को बचाने के लिए किए जा रहे इस नए काम से पता चलता है कि, भविष्य में हिम तेंदुए के संरक्षण के प्रयासों की सफलता न केवल सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, बल्कि स्थानीय लोगों के दृष्टिकोण और इसकी सुरक्षा के लिए किए जा रहे संरक्षण उपायों पर भी निर्भर करती है। उत्तर-मध्य नेपाल में अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्र देश का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यहां के स्थानीय लोग संरक्षण प्रबंधन व्यवस्था में भाग लेते हैं। हिम तेंदुओं के प्रति उनके दृष्टिकोण को पहली बार 1993 में मापे जाने के बाद से बहुत सुधार हुआ है: उत्तरदाताओं का प्रतिशत जिन्होंने कहा कि उन्हें जानवर अच्छे नहीं लगते है वे अब 60 फीसदी से नीचे गिरकर 4 फीसदी पर आगए हैं।

पराली जलाने से खुद भी शिकार हो रहे हैं किसान

प्रतिनिधि

पंजाब और हरियाणा में प्रतिबंध के बावजूद पराली जलाई जा रही है। दिल्ली-एनसीआर तक इस पराली का प्रदूषण पहुंचे, इससे पहले ही दोनों राज्यों के किसान वायु प्रदूषण के भुक्तभोगी बन रहे हैं। किसान यह भी जानते हैं कि पराली जलाने से उनकी ही सेहत को नुकसान है। इस-ाके बावजूद हर बार की तरह धान से गेहूं की फसल पर जाने के दौरान (अक्तूबर-नवंबर) किसान यह काम करते हैं।

अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के फायर इन्फॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एफआईआरएमएस) की सेटेलाइट तस्वीरें और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों से यह जाहिर होता है कि इस हफ्ते दिवाली से पहले 20 अक्तूबर से 25 अक्तूबर, 2019 के बीच पंजाब और हरियाणा के खेतों में जमकर पराली जलाई गई है। भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सों में 100 से अधिक आग लगने वाली घटनाओं में पंजाब और हरियाणा के जिले शामिल हैं।

नासा के सेटेलाइट इमेज में पंजाब के अमृतसर जिले में तरण-तारण ताल और मरी मेघा गांव के पास व फिरोजपुर जिले में जबरदस्त पराली जलाई जा रही है। इसी तरह से कपूरथला जिले में डुमियान गांव के पास पराली जलाई जा रही है। पटियाला के होडल तहसील में भी पराली जलाने के 100 से अधिक मामले आए हैं। वहीं, अंबाला में भी बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है। जबकि हरियाणा में कैथल और कुरुक्षेत्र में सर्वाधिक पराली जलाई जा रही है।

जहां पराली जलाई जा रही है क्या वहां प्रदूषण है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एक हफ्तों के आंकड़ों की पड़ताल बताती है कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में ही नहीं बल्कि उन स्थानों पर भी है जहां पराली जलाई जा रही है। वहीं, यह भी स्पष्ट है कि

पराली के कारण खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का उत्सर्जन भी होता है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों के आधार पर अमृतसर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 25 अक्तूबर को 208 दर्ज किया गया। इसमें प्रभावी प्रदूषक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है। इस जिले में 20 अक्तूबर से लगातार पराली जलाई जा रही है। 201 से 300 एक्यूआई के बीच की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में मानी जाती है। सामान्य या संतोषजनक वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 तक माना जाता है। इसी तरह पंजाब के फिरोजपुर जिले और कपूरथला जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक मापने की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां सर्वाधिक पराली जलाई जा रही है।फोटो : पराली प्रबावित पंजाब-हरियाणा के जिले अमृतसर की वायु गुणवत्ता 21 अक्तूबर से ही सामान्य नहीं है। पूरे हफ्ते वायु गुणवत्ता मॉडरेट यानी मध्यम और खराब प्रदूषण वाली ही रही है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक 113 से 240 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक मापा गया। वहीं, पराली जलाए जाने से अंबाला के हवा की स्थिति भी खराब है। यहां 25 अक्तूबर को 24 घंटों के आधार पर एक्यूआई 225 यानी खराब गुणवत्ता वाला रिकॉर्ड किया गया। पूरे हफ्ते ही एक्यूआई खराब श्रेणी 167 से 253 तक बनी रही। सभी जगह प्रभावी प्रदूषण पीएम 2.5 रहा। इसी तरह से हरियाणा में सिरसा, जींद, हिसार, कैथल और कुरुक्षेत्र में भी 20 अक्तूबर से 25 अक्तूबर तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मध्य से खराब श्रेणी के बीच झूलता रहा है। इन दोनों जिलों में 100 से अधिक बार पराली जलाए जाने के मामले सामने आए हैं। इन जिलों को छोड़कर एनसीआर के जिले पहले से ही वायु प्रदूषण के शिकार हैं। जिनका प्रदूषण ग्राफ ठंड सीजन की सुगुबुगाहट के बीच बढ़ने लगा है।आखिर किसान पराली क्यों जला रहा है?इस मामले में पंजाब के संगरुर जिले के धादरियां गांव में सरपंच गुरुचरण सिंह से इस बारे में बात की। गुरुचरण सिंह ने कहा कि प्रदूषण केवल शहर में रहने वाले लोगों को ही परेशान नहीं करता। यह उन किसानों को भी परेशान करता है जो पराली में आग लगाते हैं। हमारे बच्चे जब पराली में आग लगाते हैं, तब अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। गांव के लोगों को भी आंखों में जलन होती है और सांस लेने में दिक्कत आती है। किसान मजबूरी में पराली जलाता है। उसे पर्यावरण की फिक्र भी है और स्वास्थ्य की थी। समस्या यह है कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- Repair your laptop with 3-month warranty

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SunDAY Closed

बेवकूफी के पर्याय उल्लू की जान पर दीपावली में आफत

संवाददाता

दीपावली की रात को महानिशा भी कहा गया है। जहां एक ओर नगरों में दीपावली की रात जगमगा रही होती है वहीं तांत्रिक और अघोरी इस महानिशा की रात में श्मसान से लेकर अपने साधना स्थलों में सिद्धी के लिये तंत्र साधना करते हैं। चुंकि दीपावली में लक्ष्मीपूजन की जाती है और इस दिन मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू का देखना तक शुभ माना जाता है ऐसे में तंत्र मंत्र करने वाले दीपावली में उल्लू पर अनुष्ठान करने से लेकर इसकी बलि तक चढाते हैं। इस अंधविश्वास के कारण दीपावली पर उल्लूओं की शामत आ जाती है।

दिवाली से पहले उल्लुओं की तस्करी करते कुछ लोग पकड़े गये। गाजियाबाद की इंदिरापुरम पुलिस ने चेकिंग के दौरान दुर्लभ प्रजाति के पांच उल्लुओं के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान गाजियाबाद निवासी सुमित और प्रदीप के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दिवाली पर तांत्रिक क्रिया के बाद बलि दिए जाने के लिए ये उल्लू बेचे जाने थे। ऑन डिमांड उल्लुओं की सप्लाई करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।पुलिस के अनुसार दुर्लभ प्रजाति के इन उल्लुओं की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक करोड़ रुपये से ज्यादा है। पुलिस इस दोनों तस्करों से गहन पूछताछ कर रही है। इस तस्करी से जुड़े और लोगों की जानकारी हासिल की जा रही है। साथ ही तस्करी करके लाए गए इन उल्लुओं के खरीदारों के बारे में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि इन्हें खरीदने का ऑर्डर देने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

दिवाली में उल्लुओं की देते हैंबलि

तांत्रिकों द्वारा नीरीह उल्लूओं की बलि दी जाती है। पुलिस ने बताया कि उल्लू को लक्ष्मी का

वाहन माना जाता है। दिवाली के दिन तंत्र-मंत्र, प्रयोग और धन की देवी को खुश करने के लिए उल्लू की बलि देने की कुप्रथा प्रचलित है। इसके चलते दिवाली के दौरान उल्लुओं की तस्करी बढ़ जाती है। पुलिस ने वन विभाग के अधिकारियों को इन उल्लुओं को सौंप दिया है। अब इनको किसी सुनसान जंगली इलाके में छोड़ा जाएगा। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के दौरान उल्लुओं की तस्करी के मामले बीते कुछ वर्षों में सामने आए हैं। इसके चलते उल्लुओं की तस्करी रोकने के लिए इंदिरापुरम इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के पॉश इलाके वैशाली में उल्लुओं को ले जा रहे दो तस्करों सुमित और प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी गाजियाबाद के सिहानी गेट के रहने वाले हैं।

उल्लू की तस्करी पर सजा?

पुलिस ने बताया कि आरोपी बाइक पर एक बाल्टी में बंद करके इन उल्लुओं को ले जा रहे थे, तभी इनको वैशाली पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय वन्य जीव अधिनियम-1972 की अनुसूची-एक के तहत उल्लू संरक्षित जीव है। ये विलुप्त प्राय जीवों की श्रेणी में दर्ज है। इनके शिकार और तस्करी करने पर तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है। इनके पालने पर भी प्रतिबंध है। पूरी दुनिया में उल्लू की लगभग 225 प्रजातियां हैं। हद तो ये है कि उल्लूओं की तस्करी करने वाले खुद अपराधी होंगे, पर पढे लिखे लोग इस अंधविश्वास में कि उल्लू बलि या अनुष्ठान से वह और समृद्ध होंगे नीरीह उल्लूओं की तस्करी को बढावा दे रहे हैं।

प्लास्टिक कचड़ा बढा रही हैं कोका कोला, नेस्ले

आज प्लास्टिक हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, आप अपने चारों ओर जहां भी देख लीजिये, किसी न किसी रूप में प्लास्टिक से बनी कोई न कोई चीज दिख ही जाएगी। जहां इसने हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिया, पर साथ ही यह अपने साथ अनेको समस्याएं भी साथ लाया। उन्हीं में से एक इसके प्रदूषण की समस्या है। दुनिया के सामने यह समस्या कोई नयी नहीं है, काफी समय से हम इसके बढ़ते प्रदूषण से जूझ रहे हैं। यह न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। आज हम हर साल करीब 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा फैला रहे हैं, जो कि सम्पूर्ण मानव जाति के भार के बराबर है। इस बढ़ते प्लास्टिक कचरे के लिए कोका कोला, नेस्ले, पेप्सीको जैसे बड़े ब्रांड का सबसे बड़ा हाथ है।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः मनोज * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN00962, email:greenrevolt2019@gmail.com. Ph. 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।